[Shri R.P. Gaekwad]

ing them in this wild-life reserve, has not been served. There is constant fight between the voluntary wild life organizations and Government about the upkeep of this sanctuary ; and recently, one prominent naturalist has resigned from the Wildlife Advisory body because of difference of opinion. The Government may consider taking proper steps to ensure that the sanctuary is not destroyed by the carelessness of officials not connected with wild-life preservation. The simple questions to be answered by Government are : Why are evergreen trees along the rivers badly lopped ? Why has the lion population not increased to the extent expected ? Why are the rules and regulations applicable to other sanctuaries like Kanha or Bandhavgarh not enforced in Gir forest ? Why are crop protecting guns being issued ? Are guns necessary to scare away the deer ? Do lions destroy crops and whether the cattle population within the gir forest reserve has increased ?

I would request the Government to look into these matters for necessary action.

(iv) Need to take back in humanitarian grounds the G.R.P.F. personnel removed from service in 1979 for their agitation

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : सभापति महोदय, सन् 1979 में सैंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों ने अपनी मांगों के समर्थन में एजिटेशन किया था। इसके लिए उनमें से सैकड़ों जवानों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, और कइयों के विरुद्ध अपराध के मामले दर्ज किए गए थे। उस समय की सरकार और उस समय के सी० आर० पी० एफ० के अधिकारी इस मामले को ठीक प्रकार से निपटाने में असफल रहे थे।

वर्तमान सरकार की उदार नीति के कारण कुछ संख्या में हटाए गए जवानों को फोर्स में वापिस ले लिया गया है, बहुत से ऐसे जवान जो सेवा से हटाए गए थे और जो अपराध के मामलों में अदालतों से बरी कर दिए गए हैं, फोर्स में वापस होने का निवेदन कर रहे हैं। बेरोजगारी के कारण यह लोग बहुत परेशान हैं। इनका परिवार भुखमरी के कगार पर खड़ा हो गया है।

सरकार ने हमेशा उदार नीति अपनाते हुए रेलवे, तथा अन्य सरकारी विभागों एवं प्रतिष्ठानों के निकाले गए हड़ताली कर्मचारियों को सेवा में वापस लिया है, मेरा सरकार से आग्रह है कि वह इन लोगों पर भी दया की भावना से कार्यवाही करके इनको फोर्स में वापिस ले ले। इससे एक तरफ जहां इनके परिवारों को आर्थिक संकट से छुटकारा दिलाया जा सकेगा, वहीं दूसरी तरफ कठिन परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा और सराहनीय काम करने वाले सी० आर० पी० एफ० के जवानों में प्रसन्नता होगी और उनका मनोबल बढ़ेगा।

(v) Opening of Divisional Headquarters of Railways at Chopan (Mirzapur)

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : सभापति महोदय, मैं अपने संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र राबर्टसगंज (मिर्जापुर) के अन्तर्गत चौपन नामक स्थान में पिछले कई वर्षों से प्रस्तावित डिवीजनल हैड-क्वार्टर स्थापित करने के सम्बन्ध में माननीय रेल मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

चौपन में सारी अपेक्षाएं, जो कि एक डिवीजन के लिए आवश्यक होती हैं, उपलब्ध हैं। रेलवे डिवीजन के लिए रेल मन्त्रालय ने यहां पर पर्याप्त मात्रा में भूमि अर्जन कर रखी है। अन्य आवश्यक आधार संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चरल) सुविधाएं भी तैयार कर रखी हैं, परन्तु खेद है कि अब तक डिवीजन खोलने के सम्बन्ध में रेल मन्त्रालय का निर्णय घोषित नहीं हुआ है।

चौपन के आसपास कई सरकारी औद्योगिक संस्थान हैं, जैसे ओबरा में 1500 मेगावाट क्षमता का पावर-स्टेशन, डाला में सीमेंट फैक्टरी एवं गुरमा में सीमेंट फैक्टरी तथा क्रमशः उसके लिए रा-मैटीरियल (कच्चा माल) लाइम स्टोन की खान आदि हैं। यही नहीं, चौपन से सोन नदी गुजरती है और उससे आवश्यकतानुसार पेयजल

की व्यवस्था भी उपलब्ध है। यहां पर शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, जैसे छात्र और छात्राओं के लिए महाविद्यालय पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहां पर अधिशासी अभियन्ता (निर्माण) का भी हैड-क्वार्टर है। प्रस्तावित डिवीजन के ध्यान से यहां पर बहुत से रेलवे क्वार्टर्स भी बन गए हैं।

यहां यह बतलाना भी असंगत नहीं होगा कि चौपन आदिवासी हरिजन बाहुल्य क्षेत्र है। इसके समीप सिंगरौली कोयले की खानें तथा चार सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित हो रहे हैं। इसी प्रकार प्राइवेट सैक्टर में भी हिन्डालको, रेणु पावर प्रोजेक्ट, कनोरिया कैमीकल्स संस्थान स्थित हैं। अत: मैं रेल मन्त्री जी से चौपन में डिवीजनल कार्यालय खोलने की मांग करता हूं।

(vi) Non-utilization of money given to Haryana Government for flood Control

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : सभापति महोदय, बाढ़ देश के लिए सिर्फ प्रकृति का प्रकोप ही नहीं, बल्कि इसमें विवेक और क्रम का भी दोष है, जिसका ज्यादा सम्बन्ध सरकार से है।

पिछले साल जब हरियाणा में बाढ़ ने भयंकर रूप धारण किया तो उस सवाल को मैंने लोकसभा में गम्भीरता से उठाया। एक कमीशन मुकर्रर हुआ और मैं उस कमीशन के साथ घूमा। मुझे बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कपिल मुनि आश्रम से लेकर पद-यात्रा करनी पड़ी।

राखी गांव में उस वक्त के कृषिमन्त्री श्री आर० एफ० बेग ने मेरे 377 के उत्तर में 20 करोड़ रु० बाढ़ रोकने के लिए मंजूर करने की चिट्ठी भेजी, तब मैंने पद-यात्रा समाप्त की और वह रुपया सैंटर ने हरियाणा को दिया। परन्तु अब तक उस पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ है।

जो बाढ़ निकालने के लिए नाले खोदने थे, पूरे नहीं खुदे, बीच में रह गये, गांवों बचाने के लिए जो रिंग बांध बंधने थे, वे सही नहीं बधे, बल्कि उनमें पानी के निकास और पानी डालने के पम्प भी नहीं लगे। मिसाल के तौर पर दुबल, कालरम, ढावल, काबेखा, भाना ब्रह्मणा, मोठ, नारनोंद इत्यादि। जिला जींद व हिसार के ऐसे गांव हैं। इस प्रकार से पानी सड़ भी सकता है और गांव प्यासा भी मर सकता है।

मैं सरकार से चाहूंगा कि सरकार एक जांच कमीशन मुकर्रर कर हरियाणा में जो व्यापक तौर पर इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उसकी जांच करे। रिंग बांध और सड़कों में नीचे पाइप लाइन लगाये जिससे कि पानी निकल सके और आ सके तथा जिन लोगों ने लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए तथा बाढ़-पीड़ितों को जो अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए।

(vii) Granting finances for Banas Project to solve the drinking water problem in Jaipur

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान की राजधानी एवं विश्व-विख्यात गुलाबी नगरी जयपुर में पीने के पानी का अभूतपूर्व संकट पैदा हो गया है। 12 अगस्त से पीने के पानी का राशनिंग राज्य सरकार ने लागू कर दिया है। बीसवीं सदी से ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जयपुर जिले में वर्षा की कमी के कारण रामगढ़ बांध में पानी का स्तर सिर्फ 34 फीट है, जो अधिक से अधिक दो महीने चलेगा। अगर जल्दी प्रभावी एवं वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो जयपुर में हाहाकार मच जाएगा। यह एक अत्यन्त ही गंभीर समस्या है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए बहुत पहले बनास नदी से पानी लाने की योजना बनाई गई थी, परन्तु धनाभाव के कारण वह योजना खटाई में पड़ गई। पहले जयपुर की आबादी दो लाख थी, अब वह 12 लाख हो गई है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह जयपुर शहर की पीने के पानी की समस्या के स्थायी हल की दृष्टि से बनास योजना को पूरी करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव डाले एवं उसके लिए 2 करोड़ रु० तुरन्त मन्जूर करे।